better atmosphere in Durgapur Steel Plant. The trade unions are trying to improve that unit. the management is also trying to improve that unit and I think the basic thing that we have to consider is that the Durgapur Steel Plant is still behind other steel plants in its performance. I just want to give a couple of figures. In terms of value in 1984-85, Bhilai Steel Plant produced 840 crores worth of saleable steel, Bokaro 830 crores. Rourkela 690 crores and Durgapur 283 crores.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is because from the beginning the planning was faulty.

SHRI K. C PANT: I am quoting all the four steel plants, not just one. I think a bit of introspection will do you good. I am interested in improving this performance. I think if you shout, you cannot change these figures. Then Sir, labour cost per tonne of saleable steel is: Bokaro—459 rupees, Bhilai 777, Rourkela 853 and Durgapur 1233. So the question is, if you want Durgapur Steel Plant to come up-and I certainly do— I want it to be modernized, I want it to be rehabilitated. For that it is necessary to create a work culture in which the performance will improve, and my honourable friend will do a great service to the Durgapur Steel Plant and to the State if he creates an atmosphere in which the work culture improves, and that is my reply to all his questions.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय की बात समझ पाया तो यह कि चूंकि अब परिस्थिति अच्छी हो गई है इसलिए लाक-आउट कारन जरूरी है। अगर स्थिति अच्छी है तो लाक-आउट देर से करना चाहिए। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि तीन वर्षों में अपने देश में लाक-आउट से मानव दिनों की जो हानि हुई है वह हड़ताल की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। मंत्री महोदय ने कास्ट की भी चर्चा की है। तो लाक-आउट से तो कास्ट बढ़ती है, घटती नहीं है। जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा, ट्रेड यूनियन कोआपरेट कर रही है तो क्या मंत्री महोदय आदेश देंगे कि लाक-आउट लास्ट रिसौर्ट में होना चाहिए और सम्भव हो तो स्टील अथारिटी या मंत्री महोदय से अनुमति लेकर होना चाहिए नहीं तो इससे स्थिति और भी खराब हो रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, मैं सन्तुष्ट हूं कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। इतने पर भी करीब एक हजार टन उत्पादन का नुकसान हुआ है। करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आंकड़े हैं इसमें तो यह पब्लिक सेक्टर का नुकसान है। मुझे तो यह उम्मीद होती है कि माननीय सदस्य जोर से कहेंगे कि इस तरह से काम रोकना बड़ा गलत है और इससे सारे देश का नुकसान हो रहा है। यह उम्मीद मुझे रहती है, लेकिन मैं कभी-कभी निराश होता हूं जब मैं देखता हूं कि इस तरह की केट स्ट्राइक में भी आप जैसे जिम्मेदार लोग बजाय उसकी निन्दा करने के अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो गलत टेंडेंसी है उनको प्रोत्साहन मिलता हैं।

MR. CHAIRMAN: Next question. It is a general question. You can put more supplementatries on the next one. This relates only to Durgapur.

Modernisation of Steel Industry

*83. SHRIMATI RATAN KUMARI:

SHRI SYED RAHMATALI: + Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether a World Bank team which visited India recently has shown interest in providing assistance for the modernisation of the steel industry: and

(b) if so, what are the details in this regard?

+The question was actu lly asked on the floor of the House by Shri Syed Rahmat Ali.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) The World Bank has expressed an interest in assisting the modernisation of steel plants in India. The Bank is in the process of carrying out a study of the problems of the Indian steel industry. The question of Bank assistance for modernisation can be considered only after the study has been completed.

श्री सैय्यद रहमत अली : सरकार ने जो स्टेडी शुरू की है उसमें कितना वक्त लगेगा, यह बात मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं । अभी हाल में कोयले की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से स्टील का दाम बढ़ने का अन्देशा है उसके लिए सरकार क्या इक़दाम कर रही है यह बताएं तो महरबानी होगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभापति जी, जहां तक पहला सवाल है, अभी भी एक टीम आई है वर्ल्ड बैंक से जो बातचीत कर रही है दिल्ली के अन्दर और इस बातचीत के बाद कुछ सप्ताहों के अन्दर उनकी रिपोर्ट फाइनलाइज होगी, वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट देगी और उसी के बाद उन्होंने फैसला करना है कि वह हमारे इस्पात उद्योग को मदद करेगी या नहीं ।

दूसरा प्रश्न इससे निकलता नहीं है । अगर सभापति जी उनको इजाजत दे रहे हैं सवाल की तभी में जवाब देने की कोशिश करूंगा ।

MR. CHAIRMAN: You'd better give an answer because it deals with modernization also.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अभी दाम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है फिलहाल :

MR. CHAIRMAN: Mr. Nirmal Chatterjee.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Sir, I have asked a supplementary on the earlier question. All the same thank you very much for calling me. I take advantage if there is any mistake on the part of Chairman.

My question is: Due to modernisation of the steel industry what is the anticipated reduction in the unit cost of production of steel in India and how does it compare with the per unit cost of steel elsewhere?

SHRI K. C. PANT: Sir, that would be a very wide question. It would depend on different steel plants. It would depend on the nature of the modernisation, and I do not think one could give a general answer. But, what would be attempted in the modernisation is upgradation of technology and rehabilitation of the units where necessary. Some of these units are now over 20 years old, and unfortunately there has been a very low level of investment in these units so far as upgradation of technologyy is concerned. So, over the years the productivity of many of the constitutent units of the steel plants has fallen, and it is very necessary to rehabilitate these constituent units. Otherwise, the steady decline of the productivity and production will ultimately mean that these plants will become totally unviable. Therefore, modernisation has become an essential feature of the process of rehabilitation of our steel industry.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी, भारतवर्ष में जो स्टील प्लांट हैं अगर हम उन की दशा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जापान और हिन्दुस्तान, दोनों ने स्टील प्रोडक्शन एक साथ शुरू किया था । जापान अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण करते हुए और अपने नोहाऊ को अच्छा बनाते हुए हम से कई गुना आगे बढ़ गया है जबकि उसके पास रा मैटीरियल अपना नहीं है । लेकिन हम नोहाऊ के पिछड़ेपन के कारण आगे नहीं बढ़ पाये हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक से आधुनिकीकरण के लिये सहायता पाने के लिये जो बातचीत चल रही है उसके लिये क्या भारत सरकार जो अत्यन्त आधुनिक टैक्नोलाजी है उस के लिये बात कर रही है या कहीं जो टेक्नोलाजी समाप्त हो चुकी है और जिन लोगों ने उसके स्थान पर नयी टेक्नोलाजी शुरू कर ली है उस पुरानी टेक्नोलाजी

को ला रहे हैं और उस के लिए बात कर रहो हैं। इसलिये हमारे मंत्री जो, काफी अनुभवी रहे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष भी जापान के स्तर तक अपना आधुनिकीकरण के क्षेत्र में टैक्नोलाजी का दावा कर सकेगा? और इसी के तहत जानना चाहता हूं कि चूंकि हिन्दुस्तान की आबादी अधिक है, यहां काम करने वालों की संख्या अधिक है और आटोमाइजेशन के कारण--जो आवश्यक है आज के आधुनिकीकरण में, हमारे लोगों को काम मिलने में कठिनाई होता है और यह संका हमारे मजदूरों में बढ़ती जा रही है कि हमें काम कम मिलेगा, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात को भी सफाई करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जिस से हमारे मजदूरों की आने वाली संतति को कम काम न मिले और इसी संदर्भ में मैं बोकारो की स्थिति का भी स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभापति जी, जब आजादी के बाद तीन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने तो उस वक्त उन की टेक्नोलाजी आधुनिक कहीं जा सकती थी। जैसे रूरकेला में जो स्टील बनाने की टेक्नोलाजी लगी उस वक्त बहुत कम देश थे जिन में उस तरह की आधुनिक टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन तब से टेक्नोलाजी बहुत आगे बढ़ गयी है और आज आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि जब वे लगे थे तो उस वक्त वह आधुनिक संयंत्र नहीं थे। उस वक्त तो वे आधुनिक कारखाने थे, उन की आधुनिक टेक्नोलाजी थी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हम जापान से फिर पिछड़े कैसे हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उस वक्त, 20 साल पहले जो टक्नोलाजी थी, जापान में भी शायद उस वक्त जैसे एल०डी० कंवर्टर्स यहां है, वहां न रहे हों। आज ओपेन हार्थ फनस दुनिया से खत्म हो गये हैं लेकिन हमारे देशों में बहुत हैं। तो समय बीतता है उस के साथ ही दूसरे देशों में आधुनिकीकरण होता रहा है और इसीलिये मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा की हमारे यहां उस तरह से होता नहीं रहा। आज बहुत सी चीजें जमा हो गई हैं जिनकी वजह से आधुनिकीकरण का प्रोग्राम बना है। जो वाईजैग प्लांट बन रहा है उसमें बिलकुल आधुनिक टैक्नालोजी का इस्तेमाल करना आवश्यक है। नहीं तो उसमें स्टील बनाने का उत्पादन व्यय बहुत ज्यादा आ जाएगा इस लिये वहां आधुनिक टैक्नालोजी का यूज लेना जरूरी हो रहा है।

इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जितने श्रमिक आवश्यक हों, उतने ही उनमें रखे जाए। आधुनिकीकरण भी हो और हजारों आदमी भी रखे जायें अनावश्यक रूप से, यह तो नहीं हो सकता और आज के युग में अगर दूसरे देशों की तुलना में हम देखें तो हमारे देश में स्टील इंडस्ट्री में जितने लोग लगे हैं, उसका एक अंश लगा है दूसरे देशों में, उतने उत्पादन के लिये उन आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज यह आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि जो रोजगार बढ़ाना है वह रोजगार सस्ता इस्पात पैदा करके, उसके इस्तेमाल में जो उद्योग-धंधे लगेंगे, उनमें रोजगार बढ़ाना है और इस्पात का उत्पादन बढ़ाना है जिससे कि सारे देश में उद्योग धंधे भी फैलें, स्टील की खपत भी फैले यह रोजगार बढ़ाने का ठीक ढंग होगा। इस्पात को मंहगा बना कर हमें रोजगार को मंहगा बनाना नहीं चाहिये बल्कि अधिक रोजगार पैदा करने का तरीका अपनाना चाहिये।

SHRI JAGESH DESAI: To reduce the cost of production, production is to be increased and that can be done, provided modern technology is being utilised in the steel industry. But there are several machineries and other capital assets which can be financed through the Indian currency. Since we have to strengthen the public sector, I would like to know whether the Government or the Steel Authority is thinking of issuing bonds so that the steel industry can financed its modernisation programme and reduce the cost of production.

SHRI K. C. PANT: It is a suggestion for action.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Japan and South Korea import iron ore from outside. Both of these countries are producing steel at a much lesser cost than at what India is producing today. Can the hon. Minister enlighten us as to what are the reasons for our cost of production being so high in spite of the fact that we have our own sources of iron-ore? Secondly, the density of population in Japan is greater than what it is in our country. In spite of that they have been able to solve the problem of employing less people on the steel plants with mechanised and more sophisticated methods of producing Steel, while we still are lagging behind. Even in the public sector whereas by this time we have improved our plants and technology from time to time, we have lagged behind. What are the reasons and who are responsible for this?

SHRI K. C. PANT: Basically, I think we cannot compare the growth of the Japanese steel industry with the Indian steel industry. We, firstly, have based our steel industry entirely on our own raw materials. On the face of it that seems to be an advantage, but the fact of the matter is that we have very bad coking coal with a very high ash content and Japan has the pick of the coking coal of the world. They have turned their disadvantage into advantage. In the case of iron-ore also they have the best of iron-ore. They take our iron-ore also; and they take only the best of the Indian iron-ore. They have turned both these disadvantages into advantages.

Secondly, they are employing far lesser number of people automating far more and are using the latest technology. As I have mentioned earlier over the years we have not reinvested in improving our technology which certainly is one of the factors which has led to the difference between the growth of the Japanese industry and our industry. Now, in Korea there is a plant which has come up in recent years. It produces about 9 million tonnes of steel, employing about 12,000 persons plus 7,000 or 8,000 persons on contract labour, a total of 20,000 employees. I think the House is aware how many people we have in our steel industry and we have to redeploy them. We have to put heads together to see to make it efficient. In the new units we have to be ruthless, if I may say so, and I want the support of the House to make the new units and older units as efficient as these units are in other countries. As we modernise we should aim at achieving international standards of productivity of cost and that would entail following the same path that these countries have followed. If we are not prepared to follow the same path, then, we will be priced out and our steel industry will become a sick industry compared to these countries steel industries. It is on this realisation it must prompt all of us to come to the help of the steel industry at this critical juncture.

श्री बिट्ठलराव माधवराव जाधव : सभापति महोदय, स्टील उद्योग हमारे देश का बहुत बड़ा उद्योग है इसमें आधुनिकीकरण होना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । मैं यह जानना चाहता हुं कि आज जो हमारा भारी स्टील उद्योग है देश में उसकी जो क्षमता है स्टील प्रोडक्शन की वह पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं या नहीं ? क्योंकि मैंने देखा है जापान और साउथ कोरिया में 95 99 परसेंट कैपेसिटी से वह प्रोडेक्शन का काम करते हैं तो आधुनिकीकरण के बाद हमारे स्टील उत्पादन की क्या क्षमता होगी और कितने प्रतिशत स्टील हमारे देश में ज्यादा बढ़ेगा, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्पादन क्षमता का उपयोग पहले से बढ़ा है लेकिन अब भी संतोषजनक नहीं है । पिछले साल से उत्पादन करीब 14 फीसदी बढ़ी है लेकिन जो लक्ष्य थां उतना नहीं बढ़ा है । इसलिये अभी भी इसमें काफी आगे बढ़ने की आवश्यकता है । इस वक्त यह कोशिश हो रही है कि हर साल उत्पादन क्षमता का उप-

योग बढाया जाए । कुछ हद तक आज जैसे ये कारखाने हैं उसमें बढ़ सकता है उस हद के आगे सुधार लाने के लिये आवश्यक है कि आधुनिकीकरण हो । उसमें पैसा लगाया जाए तब उसमें सुधार पूरी तरह से आ सकता है । इसकी भी योजनाएं बनत रही हैं । भिलाई और बोकारो में इस वक्त एक्सपेंशन चल रहा है । राउरकेला और दुर्गापुर में आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं और 'इसको' को भी अगर पैरों पर खड़ा करना है तो उसका पुनरुद्धार करना होगा ।

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir I would like to know the Government's understanding or appreciation of the credentials of the World Bank to advise our country on the question of modernisation of steel plants, because it is well-known that the World Bank has been advising our country that we should "deemphasise" steel, not go for expansion of the steel industry but rather turn our attention from steel to some other things. For example, "rural oriented growth". "export oriented growth", are the slogans we have been getting from the World Bank. So, wether there is any technology in which the World Bank has specialised whicl is not known to our technicians and engineers. Whether the Government of India is going in for the World Bank advice for the sake of technology or funds? Before going in for World Bank advice, wether the Government have decided that they will not allow our steel industry to be sabotaged by the World Bank simply because they advance us some loan?

SHRI K. C. PANT: We are interested in financing the growth of our steel industry. If the World Bank gives us money on the terms which we accept then we will accept it. So far as their advice is concerned, they are bankers and presumably they are interested in the industries which they invest in any country. So,if they want to give us their opinion, if they want to give us their recommendations, they are free to do so. It is for us to see whether to accept them or not and we shall view it according to our national in terest.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir he has not answered one part.

MR . CHAIRMAN: No he has answered it very well.

Private sector entry in steel production

*84. SHRI K. MOHANAN:+ SHRI NIRMAL CHATTERJEE : Will the Minister o STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to permit private sector entry into the steel production by taking steel out of the Schedule-A of the Industrial Policy Resolution; and

(b) if so, what are the reasons therefor and when was the decision taken and at what level ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) No, Sir.

(b) Dose not arise.

SHRI K. MOHANAN : Sir, I do not know wheather there is any meaning in the 'yes' or 'no' no answer of this Government because they are saying something yes today and the next moment, they are going exactly against that. But, here, my question is that I would like to know from the Government whether there is any serious proposal from the any Ministry of steel. to take the Steel industry from Schedule A of the 1965 Industrial Policy Resolution and whether the proposal mooted from the Steel Ministry is under the consideration of the Government.

SHRI K. C. PANT : Sir, this I could easily answer by saying 'no' and end the matter. But in fairness to my honble Member I think. I should explain to him the change

+The question was actually asked on the floor of House by Shri K. Mohnan